

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 512/2025

अरविन्द कुमार

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए अतिरिक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन) , कृषि आयुक्तालय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, बूंदी।
3. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), बूंदी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.02.2025

आदेश की दिनांक : 24.02.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री पी आर कुमावत, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य

असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय थाना सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), बूंदी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मुख्यालय पढाना, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सवाई माधोपुर में रिक्त पद पर किया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती कंचन कुमारी मीणा राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पंचायत समिति हिण्डोली, जिला बूंदी में कार्यरत है (अनुलग्नक-2) तथा अपीलार्थी की दो पुत्रियां जो क्रमशः 5 वर्ष एवं 2 वर्ष की है (अनुलग्नक-3 एवं 4) एवं अपीलार्थी के पिता मिर्गी रोग से ग्रसित है (अनुलग्नक-5)। अपीलार्थी का

- आगे कथन है कि राज्य सरकार की नीति रही है कि यदि पति-पत्नी राजकीय सेवा में कार्यरत है तो यथासम्भव उन्हें एक ही स्थान या निकटस्थ स्थान पर कार्यरत रखा जावे। इस आधार पर आलोच्य आदेश राज्य सरकार की सामान्य स्थानांतरण नीति की अवहेलना में जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) विधि-विरुद्ध है।
4. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) को अपास्त कर अपीलार्थी को कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय थाना सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), बूंदी में कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।
 5. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
 6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
 7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य